डिसकस करके रीजनेबल बनाया जाये ताकि लोग इसको कंवर्ट करा सके। कोई फायदा नहीं है फ्री होल्ड कराने में कामर्शियल लीज को। यह फ्री होल्ड हो या न हो किसी को क्या फर्क पड़ता है। सवाल गवर्नमेंट के ब्लैक मेलिंग का है और इस वजह से आप इसको रेगुलराइज करिए, रेट कम करिए और रूल्स ऐसे बनाइये कि जो बीच में बैठकर वहां पर एजेन्ट दस-दस और बीस-बीस हजार रुपया ले रहे हैं उसको खत्म किया जाये। इसको आप कब तक करें गे? मंत्री महोदया यहां पर बैठे हैं वे इसको एश्योर करें। यह मैं डिमांड करना चाहता हूं।

श्री ओ॰पी॰ कोहली (दिल्ली): मैं प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य से अपने को सहमत करता हूं कि मास्टर प्लान में संशोधन होना चाहिये। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कंवर्जन की जो तारीख है इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिये। कल भी मास्टर प्लान में संशोधन का विषय यहां पर उठाया गया था। इसके बिना उस समस्या का समाधान नहीं है। जो सवाल अभी यहां पर इंडस्ट्री का उठाया गया है उसमें करीब दस लाख मजदूर काम करते हैं। उनके भविष्य का सवाल है और एक लाख इंडस्ट्री के बन्द होने का सवाल है। मास्टर प्लान में संशोधन ही इसका एक मात्र उपाय है और साथ में ही लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कंवर्जन की तिथि को भी बढ़ाया जाना चाहिये। मैं प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य से अपने को एसोसिएट करता हूं।

उपसभापति: श्री सतीश प्रधान।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा। मैडम, मंत्री जी हैं।Kindly ask the Minister whether he wants to say something, in this regard कि वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पिछले 6 महीने से?... (**व्यवधान**)

उपसभापति: श्री सतीश प्रधान।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा। नहीं, नहीं। मिनिस्टर साहब से पूछिये तो सही।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Had he wanted to say something, he would have said it.

RE: CIRCULATION OF FAKE Rs. 500 AND Rs. 100 CURRENCY NOTES BY PAKISTAN

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): महोदया, मैं इस सदन में रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेटमेंट के विषय पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट निकाली और बताया कि पाकिस्तान और उनका आई॰एस॰आई॰ हिन्दुस्तान में रिटेल मार्किट में खासकर के सौ रुपया और पांच सौ रुपया के जाली नोट सर्कुलेट कर रही है। मुझे याद है कि हम जिस ढंग से नोट निकालते हैं, छापते हैं और बनाते हैं, उस विषय पर मैंने पिछले कई सेशनों में इस सदन में एक विषय रखा था और उसमें बताया था कि हमारे यहां जो नोट बनते हैं उनमें कैसे फर्क रहता है। मैंने यह सदन के सामने लाने की कोशिश की थी और उस समय भी बताया था कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री इस विषय पर ध्यान दें और हमें बतायें कि सच क्या है? अभी तो रिजर्व बैंक बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहां जाली नोट फैलाने की सर्कुलेट करने की कोशिश हो रही है। रिजर्व बैंक लोगों को सतर्क कर रहा है कि आप इस विषय पर सतर्क रहें। इससे यहां कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि हमारे पास जो हमारी खुफिया एजेंसिज हैं ये इस विषय में क्या कर रही हैं, हमारा पुलिस डिमार्टमेंट क्या कर रहा है?

ये जाली नोट यहां सर्कुलेट न हो या इनको बन्द करने की सरकार क्या कोशिश कर रही है, इस विषय पर यहां आकर सरकार को स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है। अभी तक सरकार का इस विषय पर आगे क्या कुछ करने का इरादा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सदन में आकर इस विषय पर जो असलियत है वह सबके सामने रखे क्योंकि यह रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट है और किसी के द्वारा जारी किया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। जब रिजर्व बैंक स्टेटमेंट जारी करता है तो इसका मतलब यह है कि यह सच है। यदि यह सच है तो इस विषय पर सरकार को पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी है और उसको सदन में आना होगा और इस विषय पर जानकारी देनी होगी।

RE: NEED TO BRING LEGISLATION FOR RESERVATION FOR DALIT CHRISTIANS IN THE CURRENT SESSION OF PARALIAMENT

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई आपस में सब भाई-भाई, ये नारा दिवारों पर तो लिखा गया लेकिन दिलों पर शायद इस नारे को लिखने की फुर्सत नहीं मिली है। अभी एक रोज पहले 27 तारीख को देशभर के गिरजाघरों के पादरियों, नन्स ने यानी अगर कहें कि क्रिश्चियन्स बिरादरी के सैकड़ों पुरूषों और महिलाओं ने दिल्ली की सड़कों पर एक मार्च किया और संयुक्त मोर्चा की सरकार को उनके वायदे की याद दिलाई।

वह यह था कि मिनिमम प्रोग्राम के तहत क्रिश्चियनों में जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं उनको भी मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात देश के समाचार-पत्रों में छपी और देश के लोगों तक आई तो कुछ संगठनों ने इसका बड़ी ही सख्त विरोध किया और कहा कि इससे धर्म परिवर्तन को सहारा मिलेगा। कुछ लोग क्रिश्चियन होकर, मज़हब बदलकर इस राहत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसका एक अच्छा खासा माहोल देश में बना और मोर्चे का किया हुआ वायदा रह गया और एक ऐसी भावना उभरकर सामने आई जिसने 47 के बाद देश को काफी कमज़ोरी का सामना करना पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा और इसमें जानना भी चाहूंगा कि इस 90-95 करोड़ के देश में मज़हबों के बहुत से इख्तिलाफ हैं, अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग नस्लों के लोग हैं। कुछ लोगों को बाहर से आया हुआ बताया जाता हैं और कुछ लोगों को यहां की पैदावार बताया जाता है। लेकिन हैं सब हिन्दुस्तानी। धर्म परिवर्तन के बाद उनकी शहरियत नहीं बदल जाएगी, उनकी वतनियत नहीं बदल जाएगी। उनका आसमान हिन्दुस्तान की ज़मीन के ऊपर का आसमान होगा। रोशनी उसी सूर्य की होगी और उसी चांद की ठंडक होगी। अगर हमारी यह मंशा है कि हिन्दी हिन्दू हिन्दूस्तान तो फिर बाकी यहां रहने वाले इंसानों के लिए हिन्दुस्तान में क्या जगह होगी। मैं साम्प्रदायिकता की बात करने वाले लोगों से जानना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसा माहोल बना दिया कि बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग, एक बहुत ही कम तादाद में रहने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर आए। मैं उन नन्स की बात कहता हूं जो कि बहुत कम बाहर निकलती हैं, यही उनकी पहचान हैं दिल्ली की सड़कों पर उनको देखकर किसी को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। यह जो हुआ यह बहुत डीसेंट नहीं हुआ। उन्हें सरकार का अपना वायदा याद दिलाने के लिए आना पड़ा, उसके लिए यह नौबत पेश आई। चुनांचे मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं उनके लिए धर्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस बुनियाद पर अगर समाज के इस कमज़ोर तबके का उठाने की बात की जाए तो यह गलत नहीं होगा। मंडल कमीशन की सिफारिशें इसलिए नहीं हुई हैं कि वे इससे कोई सियासी फायदा उठाना चाहते थे या किसी वर्ग को सत्ता से हटाकर किसी वर्ग को सत्ता में लाना चाहते थे। आम ज़िंदगी में यह होता है कि कमज़ोर बच्चा अगर घर में पैदा होता है कि उसके लिए दवा का इंतज़ाम अलग से होता है, उसके लिए दूध का इंतज़ाम अलग से होता है, उसके लिए फलों का इंतज़ाम अलग से होता है। चुनांचे यह कहना कि रिज़र्वेशन देकर कोई सियासी कदम उठाया गया है, यह बिल्कुल सही नहीं है। हम देश की ज़िन्दगी में कमज़ोर वर्गों के लिए अलग से कुछ करेंगे क्योंकि पूरा देश एक परिवार है और सरकार उसकी मुखिया की हैसियत रखती है। चुनांचे सरकार एक मुखिया की हैसियत में रहते हुए देश में रहने वाल तमाम कमज़ोर तबकात-बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरी दुनियां के देशों में जो अकलियत हैं, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनारिटीज कहते हैं, उनके लिए खास अख्तियारात हैं। जब हमारा दस्तूरे हिन्द बना तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि अल्पसंख्यक तालीमी तौर पर पिछड़े न रहें, अल्पसंख्यक मांसी तौर पर पिछड़े न रहें, समाजी तौर पर पिछड़े न रहें और उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव न हो जिससे ज़बरन उनको मजहब बदलकर - जैसे उन्हें कभी कभी मेन धारा में लाने की बात होती है, इसके लिए उन्हें मजबूर न किया जा सके क्योंकि सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज, सबसे अहम चीज है इंसान की जिंदगी। अगर ज़िंदा रहने के लिए लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वह किसी खास अंदाज से जियें तो जब लोग अपनी जिंदगी की डर से तंग होते हैं तो हो सकता है कि वे अपने आप को बदलने पर आमदा हो जायें। लिहाजा देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, कमजोर लोग हैं उनको यकीनन यह हक़ होना चाहिए और उनका यह हक है कि वह सरकार से मांग करें कि उनको भी जमाने के साथ चलने और राहतों के वह सारे जराय मुहैया हों जो दूसरे लोगों को है। चुनांचे मैं इस जीरो आवर के माध्यम से, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से दो रोज पहले दिल्ली में जो मार्च हुआ है, आपका वायदा भी है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार से मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत वे सारी सहूलियतें मिलेंगी जो दूसरी कम्युनिटी को हासिल है, जो दूसरे वर्गों को हासिल है। ये सहूलियतें उनको भी मिलनी चाहिए। वायदे पूरे ही नहीं होने चाहिए बल्कि वायदा वफा होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : महोदया, मैं इससे अपने का एसोसियेट करती हूं।

Re. Difficulties Faced by Cardamom Growers due to Smuggling of Guatemala Cardamom to India

SHRI JOY NADUKKARA (Kerala): Madam, thank you for giving me this opportunity. I would like to bring to the notice of this House certain problems the cardamom